PM सूर्य घर: 27 जुलाई 2026 तक प्रतिष्ठापन और सहायता की स्थिति

ऊर्जा / आवास / केंद्रीय वित्तीय सहायता | समाचार संदर्भ: PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना पर लोक सभा के दो उत्तर, 29 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

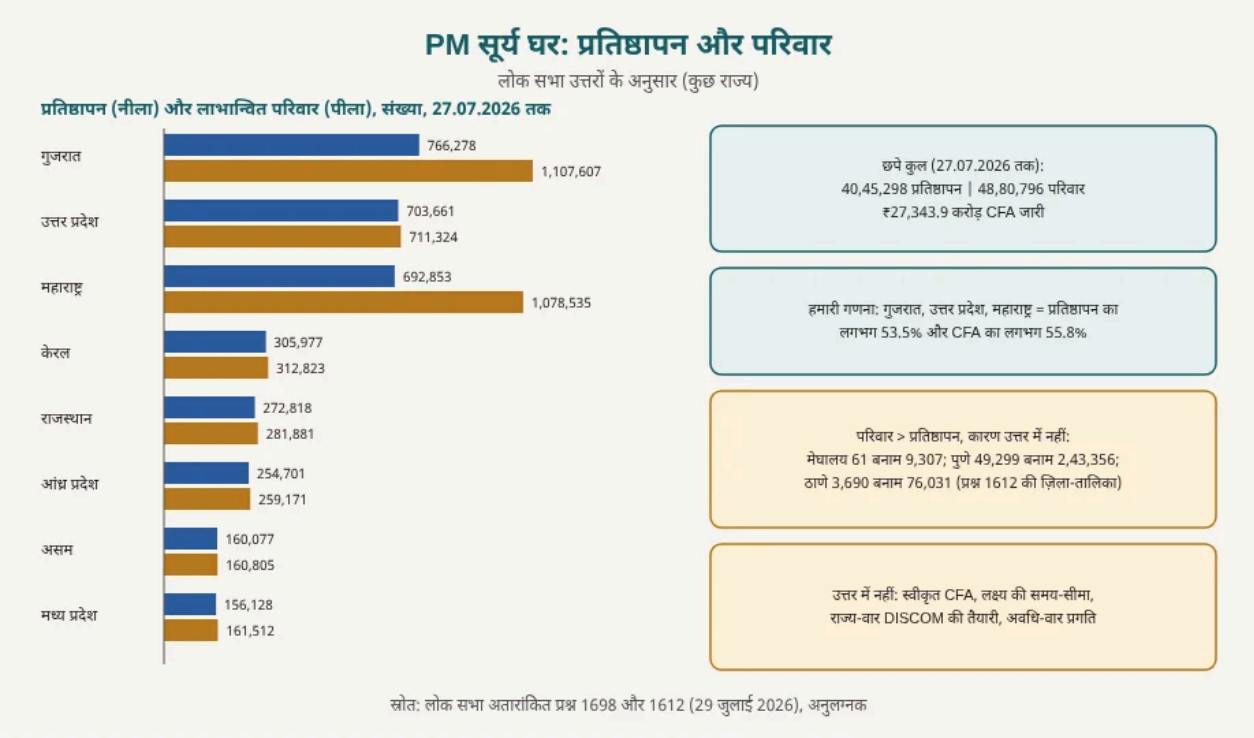
PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PMSG: MBY) में घरों की छत पर सौर प्रणाली (RTS) लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) मिलती है। उत्तर के अनुसार योजना फ़रवरी 2024 में शुरू हुई, यह माँग-आधारित है और राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन से सहायता के भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन है। इस लेख का आधार लोक सभा के दो उत्तर और उनके अनुलग्नक हैं।

खबरों में क्यों

29 जुलाई 2026 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1698 (डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन; “Review of Progress of Rooftop Solar Installations”) और प्रश्न 1612 (श्री हरिभाई पटेल सहित अनेक सदस्य; “Implementation of PM-SGMBY”) के उत्तर दिए। प्रश्नों में राज्य-वार प्रगति, परिवारों की संख्या, जारी सहायता, बाधाएँ और सुधार के कदम पूछे गए थे; प्रश्न 1612 में स्वीकृत सहायता, सहायता के निपटान का औसत समय, ज़िला-वार ब्योरा, लक्ष्य की समय-सीमा, उत्सर्जन में कमी और सीधी लोक सभा क्षेत्र (सीधी) का ब्योरा भी पूछा गया था।

मुख्य अवधारणा: “प्रतिष्ठापन” और “परिवार” की संख्याएँ एक जैसी नहीं हैं

दोनों उत्तर कहते हैं: “a total of 40,45,298 RTS systems have been installed, benefitting 48,80,796 households, and an amount of Rs. 27,343.9 crore has been released as Central Financial Assistance (CFA) ... as on 27.07.2026.” अनुलग्नक में परिवारों की संख्या प्रतिष्ठापनों से अधिक है: जैसे गुजरात में 7,66,278 प्रतिष्ठापन और 11,07,607 परिवार, महाराष्ट्र में 6,92,853 और 10,78,535, मेघालय में 61 और 9,307। ज़िला-वार तालिका में पुणे में 49,299 प्रतिष्ठापन और 2,43,356 परिवार तथा ठाणे में 3,690 और 76,031 छपे हैं। उत्तर इन अंतरों का कारण नहीं बताता और हमने कोई कारण नहीं माना।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

राष्ट्रीय कुल (उत्तर, 27.07.2026 तक)	**फ़रवरी 2024 में शुरुआत के बाद 40,45,298 RTS प्रतिष्ठापन; 48,80,796 परिवार; ₹27,343.9 करोड़ CFA जारी।**
सबसे अधिक राज्य (छपे)	प्रतिष्ठापन: गुजरात 7,66,278; उत्तर प्रदेश 7,03,661; महाराष्ट्र 6,92,853; केरल 3,05,977; राजस्थान 2,72,818। CFA (₹ करोड़): गुजरात 5,597.04; महाराष्ट्र 5,017.02; उत्तर प्रदेश 4,652.73; केरल 2,043.61; राजस्थान 1,815.39।
संकेंद्रण (हमारी गणना)	गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का प्रतिष्ठापन-जोड़ 21,62,792 यानी कुल का लगभग 53.5%; इन्हीं तीन राज्यों की CFA का जोड़ ₹15,266.79 करोड़ यानी कुल का लगभग 55.8%। यह राज्य-वार बँटवारे का वर्णन है, राज्यों की आबादी या घरों की संख्या से तुलना नहीं।
छोटे आँकड़े (छपे)	अरुणाचल प्रदेश: 1 प्रतिष्ठापन, 1 परिवार, ₹0.01 करोड़; सिक्किम: 59, 59, ₹0.37 करोड़; मेघालय: 61 प्रतिष्ठापन, 9,307 परिवार, ₹0.31 करोड़।
ज़िला-वार तालिका (प्रश्न 1612, छह राज्य)	राजस्थान 41, उत्तर प्रदेश 75, महाराष्ट्र 36, हिमाचल प्रदेश 12, तेलंगाना 33 और मध्य प्रदेश 55 ज़िलों की पंक्तियाँ। परिवारों की संख्या प्रतिष्ठापनों से अधिक वाले ज़िले: राजस्थान 16, उत्तर प्रदेश 25, महाराष्ट्र 30, हिमाचल प्रदेश 9, तेलंगाना 13, मध्य प्रदेश 10 (हमारी गणना)।
सीधी लोक सभा क्षेत्र (उत्तर, प्रश्न 1612)	27.07.2026 तक 1,818 प्रतिष्ठापन, 1,818 परिवार और ₹12.7 करोड़ CFA।
निपटान का समय और अनुमान (उत्तर, प्रश्न 1612)	ऑनलाइन प्रक्रिया में सभी विवरण सही दर्ज होने पर “average time taken in releasing the CFA is around 15 days after redemption request made by the consumer”। अनुमान: एक करोड़ परिवारों में RTS प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवन-काल में 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली “may

	produce” और 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी “may result”; यह अनुमान है, मापा हुआ परिणाम नहीं।
उठाए गए कदम (उत्तर)	पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया; रेपो दर जमा 50 आधार अंक (वर्तमान में 5.75% वार्षिक) पर 10 साल की बिना-जमानत ऋण सुविधा; तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त हटाना और 10 kW तक स्वतः लोड-वृद्धि; नेट मीटरिंग समझौता आवेदन का हिस्सा; विक्रेता पंजीकरण सरल; प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान; निगरानी और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें; शिकायत निवारण (कॉल सेंटर 15555, 12 भाषाओं में)।

आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं

जो मेल खाता है (हमारी गणना, दो विधियों से): दोनों उत्तरों के अनुलग्नक-1 की 36 पंक्तियाँ एक-जैसी हैं। उनका जोड़ प्रतिष्ठापन में 40,45,298 और परिवारों में 48,80,796 है, जो छपे कुल हैं। CFA का जोड़ ₹27,343.88 करोड़ है, जबकि छपा कुल एक दशमलव तक ₹27,343.9 करोड़ है। ज़िला-वार तालिकाओं में पंक्तियाँ पूरी गिनी गईं; प्रतिष्ठापन और परिवारों का जोड़ छहों राज्यों में छपे राज्य-कुल से ठीक मिलता है।

जो मेल नहीं खाता: ज़िला-वार CFA का जोड़ चार राज्यों में छपे कुल से थोड़ा अलग है: राजस्थान 1,815.41 बनाम 1,815.39; उत्तर प्रदेश 4,652.76 बनाम 4,652.73; हिमाचल प्रदेश 87.01 बनाम 87.00; तेलंगाना 325.12 बनाम 325.11 (₹ करोड़)। छपा पाठ कारण नहीं बताता और हम इसे गोलाई नहीं कह रहे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोड़ ठीक मिलता है।

पूछा गया बनाम दिया गया: प्रश्न 1612 में स्वीकृत (sanctioned) CFA, पूरे देश के ज़िला-वार ब्योरे, लक्ष्य की समय-सीमा और कम प्रदर्शन वाले राज्यों में DISCOM की तैयारी माँगी गई थी; उत्तर में जारी CFA, छह राज्यों के ज़िले, सामान्य कदमों की सूची और अनुमान हैं, पर स्वीकृत राशि, लक्ष्य की समय-सीमा और राज्य-विशेष DISCOM ब्योरा नहीं।

अवधि: सभी आँकड़े 27.07.2026 तक के हैं और दोनों उत्तर 29.07.2026 के हैं। शुरुआत से अब तक का संचयी आँकड़ा है; साल-वार या अवधि-वार बँटवारा नहीं दिया गया।

महत्व: एक योजना के भीतर इकाइयों का फ़र्क़

गणना की इकाई: प्रतिष्ठापन प्रणालियों की गिनती है और परिवार लाभार्थियों की; दोनों बराबर मानकर प्रति-परिवार सहायता या औसत आकार निकालना उत्तर के आधार पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमने ऐसा अनुपात नहीं बनाया।

राज्यों में असमान वितरण: तीन राज्यों में प्रतिष्ठापन और CFA दोनों का आधे से अधिक हिस्सा है (हमारी गणना), जबकि अरुणाचल प्रदेश में एक प्रतिष्ठापन है। उत्तर वितरण के कारण या राज्यों की संभावित क्षमता नहीं बताता।

चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है

पूछा गया, पर नहीं मिला: स्वीकृत CFA की राशि; पूरे देश के ज़िला-वार आँकड़े; लक्ष्य की समय-सीमा; राज्य-वार DISCOM की तैयारी और ग्रिड-संपर्क की स्थिति; कम प्रदर्शन वाले राज्यों की सूची; वार्षिक या अवधि-वार प्रगति।

अनसुलझे बिंदु: परिवार और प्रतिष्ठापन की संख्या में अंतर का कारण (गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, पुणे, ठाणे आदि); ज़िला-वार CFA जोड़ में 0.01 से 0.03 करोड़ का अंतर; “15 days” की औसत गणना की विधि और अवधि।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने केवल लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1698 और 1612 के आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े। योजना के दिशानिर्देश, राष्ट्रीय पोर्टल के आँकड़े और मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं पढ़े गए।

आगे की राह

इसे 29 जुलाई 2026 के उत्तरों की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; स्वीकृत सहायता, लक्ष्य-समय और परिवार-प्रतिष्ठापन के अंतर की परिभाषा तब देखी जा सकेगी जब मंत्रालय उन्हें प्रकाशित करे।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) प्रतिष्ठापन की संख्या; (2) लाभान्वित परिवारों की संख्या; (3) जारी CFA (स्वीकृत राशि उत्तर में नहीं); (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।

मेंस दृष्टि

GS-III: ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन और बुनियादी ढाँचा; GS-II: केंद्र-राज्य संबंध और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के राज्य-वार और ज़िला-वार आँकड़ों से प्रगति के बारे में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं? योजना के आकलन के लिए किन अतिरिक्त आँकड़ों की ज़रूरत होगी?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: योजना और प्रश्न 1698, 1612 (29.07.2026)।

मुख्य भाग में: 27.07.2026 तक 40,45,298 प्रतिष्ठापन, 48,80,796 परिवार, ₹27,343.9 करोड़ CFA; तीन राज्यों में आधे से अधिक (हमारी गणना); परिवार और प्रतिष्ठापन के अंतर (गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, पुणे, ठाणे); ज़िला-वार जोड़ के अंतर; पूछा गया बनाम दिया गया (स्वीकृत राशि, लक्ष्य-समय, DISCOM); ज़रूरी अतिरिक्त आँकड़े।

निष्कर्ष में: प्रतिष्ठापन, परिवार और जारी CFA योजना की प्रगति के अलग संकेतक हैं; परिभाषाएँ, स्वीकृत सहायता और लक्ष्य-समय स्पष्ट हुए बिना इनके अंतर से लक्ष्य-पूर्ति या राज्यवार सफलता का निश्चित दावा न करें।

स्रोत

- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1698 और उत्तर, 29.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; अनुलग्नक सहित)
- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1612 और उत्तर, 29.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; अनुलग्नक I-II सहित)

स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1698 और 1612 के आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े गए और जोड़ जाँचे गए। दिशानिर्देश और पोर्टल के आँकड़े नहीं पढ़े गए।

याद रखें: लोक सभा उत्तरों के अनुसार 27.07.2026 तक PM सूर्य घर में 40,45,298 प्रतिष्ठापन, 48,80,796 परिवार और ₹27,343.9 करोड़ की CFA जारी है; परिवार और प्रतिष्ठापन की संख्याओं में अंतर, स्वीकृत राशि और लक्ष्य-समय उत्तर में स्पष्ट नहीं हैं।